(ख) क्या ये सभी बैंक देश के ग्रामीण लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण और अन्य बैंकिंग सहायता प्रदान करते हैं; और

(ग) हरियाणा स्थित इन बैंकों को ग्रामीण लोगों से अब तक कुल कितने ऋण-आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा इन लोगों को कितनी अवधि के भीतर ऋण दे दिया गया अथवा ऋण देने से मना कर दिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबी प्रसाद पाल): (क) देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। 1987 से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के लिए निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है:

(i) सीमांतिक किसानों के कृषि ऋणों के प्रयोजन के लिए ऋण अंतराल की राशि, (ii) जिले में सहकारी ऋण संस्थाओं की संख्या (iii) ऋण निवेश के लिए लोगों की ऋण की जरूरतें, (iv) वर्तमान सेवा क्षेत्र का कवरेज आदि।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक नीचे दिए गए हैं:

(i) छोटे और सीमांतिक किसानों का अधिक अनुपात (ii) कृषि मजदूरों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अधिक अनुपात (iii) सहकारी समितियों की अधिक अतिदेय राशियां और सहकारी समितियों द्वारा प्रदान किए गए प्रति हेक्टेयर अल्पावधिक ऋणों का निम्न स्तर (iv) वाणिज्यिक बैंकों का शाखा नेटवर्क (v) क्षेत्र का पिछड़ापन/क्षेत्र में उपलब्ध उपयुक्त क्षमता।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रमुख उद्देश्य मुख्यतः लघु एवं सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, शिल्पियों और छोटे उद्यमियों को कृषि, व्यापार, उद्योग एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य उत्पादकता के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाएं देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचना दी है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास दिनांक 31.3.95 की स्थिति के अनुसार, 125.92 लाख ऋण खाता में कुल 6290.22 करोड़ रुपए की ऋण राशि बकाया है। लघु एवं सीमान्त किसानों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को दिए गए ऋण का काफी प्रतिशत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिया जाता है।

(ग) हरियाणा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण-आवेदन पत्रों की संख्या के संबंध में आंकड़े नाबार्ड के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, दिनांक 31.3.94 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 435,996 ऋण खातों में कुल बकाया अग्रिम राशि 165.10 करोड़ रुपए है। वर्ष 1993-94 के दौरान 45883 खातों में 58.04 करोड़ रुपए के ऋण दिए गये। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 25,000/- रुपए से कम के ऋण आवेदन पत्रों को 2 सप्ताह के भीतर निपटा दें। 25,000 रुपए से अधिक के ऋण आवेदन पत्र 8 से 9 सप्ताह के अंदर निपटाए जाने चाहिए।

विदेशी ऋण और सकल घरेलू उत्पाद

64. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों से देश पर विदेशी ऋणों की राशि में निरंतर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान देश पर कुल कितना विदेशी ऋण था तथा यह उस वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था; और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान अनुमानित विदेशी ऋण कितना है और यह इस वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबी प्रसाद पाल): (क) पिछले कई वर्षों से बढ़ते रहने के बाद अमरीकी डालर के रूप में, विदेशी ऋण में 31.3.95 से 30.9.95 के बीच 5.2 बिलियन अमरीकी डालर की कमी आई।

(ख) 31.3.1991 को कुल विदेशी ऋण 83.8 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है। यह 1990-91 के सकल घरेलू उत्पाद का 30.4 प्रतिशत बनता है।

(ग) अद्यतन अनुमानों के अनुसार 30.9.95 को कुल बकाया विदेशी ऋण 93.8 बिलियन अमरीकी डालर है। यह 1995-96 के अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 29.4 प्रतिशत बनता है।

Depreciation of Rupee Against U.S. Dollar

65. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the rupee is drastically depreciated against the U.S. dollar;

(b) Government's reaction thereto;

(c) What is the exchange value of dollar in terms of rupees as on date in comparision to that obtaining during the last three years; and

(d) the impact on the country's trade, economy and balance of payments as a result of the depreciation of rupee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) and (b) After prolonged period of stability between March 1993 and July 1995, the exchange rate of the rupee against the US dollar depreciated in the following months. The depreciation is a market correction for the real appreciation in the external value of the rupee that had taken place since 1993-94 due to inflation differentials between India and the major trading partner countries. There was, however, excessive volatility in the exchange rate in recent periods due to speculative factors which were actively countered by the RBI through appropriate measures.

(c) The exchange rate of the rupee was Rs. 36.560 per US dollar on February 23, 1996. This compares with the average rate of Rs. 30.6488 per US dollar for 1992-93. Rs. 31. 3655 per US dollar for 1993-94 and Rs. 31.3986 per US dollar for 1994-95.

(d) The recent change in the exchange rate has corrected the erosion in India's competitiveness and will help ensure that export growth remains strong and import growth is contained. Both factors will help to contain the trade deficit to manageable levels and to achieve a viable balace of payment based on strong competitiveness.

Excise Claims Against New Tobacco Company

66. SHRI CHATURANAN MISHRA: SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an excise claim of about Rs. 250 crore against the New Tobacco Company previously National Tobacco Company Limited; and

(b) if so, when the claim was made and what steps are being taken for the recovery of this amount?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Central Excise claims amounting to Rs. 59.46 crore (Confirmed demands) excluding penalty are outstanding against M/s New Tobacco Company Limited as on date.

(b) Various claims were made against the Company in various periods from 1987 to date. Necessary administrative, legal and other measures under the relevant laws/Acts are continuously taken to recover the outstanding dues.

Interim Report of Fifth Pay Commission

67. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under Government consideration to get an Interim Report from the Fifth Pay Commission containing recommendations on the age of retirement, pensionary benefits and merger of DA, Interim Relief into pay for pension purposes, if so, the details there of and if not the reasons therefor; and

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government/ Fifth Pay Commission to increase retirement age of Government